

प्रेषक,

भास्करानन्द,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
उत्तरकाशी।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 28 फरवरी, 2013

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2012-13 में जनपद उत्तरकाशी क्षेत्रांतर्गत प्राकृतिक आपदा बाढ़ एवं बादल फटने से क्षतिग्रस्त पुलों के निर्माण कार्य हेतु एन.बी.सी. सी. द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणनों के सापेक्ष 10% धनराशि बतौर मोबिलाइजेशन एडवांस की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-723, दिनांक 20.12.2012 द्वारा जनपद उत्तरकाशी में अतिवृष्टि एवं बादल फटने के कारण आयी भीषण प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लि0 को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। उक्त कार्यदायी संस्था द्वारा अपने पत्र संख्या-NBCC/GM/UK/HDUK/2013, दिनांक 31 जनवरी, 2013 के माध्यम से 14 पुलों के निर्माण कार्य हेतु कुल ₹ 60.87 करोड़ के प्रारम्भिक आगणन/प्रस्ताव धनावंटन की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये हैं। प्रश्नगत प्रकरण में उच्च स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक आगणन की लागत का 10% अर्थात् ₹ 6.00 करोड़ (₹ छः करोड़ मात्र) की धनराशि बतौर मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में उक्त कार्यदायी संस्था को भुगतान किये जाने हेतु आपके निर्वर्तन पर निम्नलिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. धनराशि का आहरण कार्यदायी संस्था के साथ एम.ओ.यू. किये जाने के उपरान्त ही किया जायेगा।
2. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के शासनादेश संख्या-32-7/2011-NDM-I, दिनांक 16 जनवरी, 2012 के माध्यम से राज्य आपदा मोचन निधि से धनराशि स्वीकृत/व्यय किये जाने सम्बन्धी मानक पुनरीक्षित कर दिये गये हैं। जिसकी प्रति आपको पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है, का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
3. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाओं से हुई क्षति में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से व्यय हेतु संशोधित दिशा-निर्देशों के बिन्दु संख्या-10 में भारत सरकार द्वारा विभागवार तात्कालिक प्रकृति के कार्य स्पष्ट किये गये हैं तथा तात्कालिक प्रकृति के क्षतिग्रस्त कार्यों में मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु समय सीमा निर्धारित की गयी है। अतः प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि तात्कालिक प्रकृति के क्षतिग्रस्त कार्यों यथा-मार्गों एवं पुलों, पेयजल आपूर्ति से संबन्धित अवसंरचनायें (हैण्ड पम्प, कुएँ, टैंक, क्षतिग्रस्त पाइप लाइन इत्यादि), विद्युत (केवल ऐसे क्षेत्रों जहाँ तात्कालिक रूप से विद्युत व्यवस्था की जानी होगी), प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों, पंचायतों की सामुदायिक परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु धनराशि व्यय की जायेगी तथा निर्धारित अवधि में ही मरम्मत कार्य पूर्ण किये जायेंगे।



4. आहरण व व्यय केवल उन सरम्मत/पुनर्स्थापना कार्यों के लिए किया जायेगा, जो एस.डी.आर.एफ. के दिशा निर्देशों में अनुमन्य हैं एवं जिनके लिए राज्य स्तरीय समिति से नियमानुसार आवश्यकता का आंकलन करा लिया गया हो और व्यय आंकलन के अनुसार ही किया जायेगा।
5. कार्यदायी संस्था/निर्माण एजेंसी द्वारा प्रस्तुत कार्य के विस्तृत आगणन (डी0पी0आर0) के अनुसार उक्तानुसार स्वीकृत प्रारम्भिक आगणन की धनराशि का समायोजन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
6. सरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के साथ आहरित की जायेगी-
  1. आगणन में उल्लिखित दरों के विश्लेषण को संबंधित विभाग के अधिशासी अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य प्राप्त की जाय।
  2. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
  3. कार्य कराने से पूर्व कम से कम अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर लें तथा यह सुनिश्चित करें कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये हैं वह स्थल की आवश्यकतानुसार हैं अथवा नहीं। स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित करें।
  4. कार्य कराने से पूर्व स्थल का आवश्यकतानुसार विस्तृत आगणन/माचघिन्न गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लें, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय। जिन आगणनों में स्लिप लिया गया है, कार्य कराने से पूर्व माप पुस्तिका से रिकार्ड मेजरमेंट इंगित अवश्य कराये जाय तथा इसका सत्यापन अधिशासी अभियन्ता स्वयं करें।
  5. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय। एक मद की राशि का उपयोग दूसरी मदों में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिलाधिकारी एवं निर्माण ईकाई का होगा।
  6. स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त है तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों से आच्छादित है। स्वीकृत धनराशि नव निर्माण कार्यों में कदापि व्यय नहीं की जायेगी तथा गत वर्ष की योजनाओं हेतु धनराशि स्वीकृत न की जाय।
  7. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट अथवा इस बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। यदि स्वीकृति प्राप्त हुई है तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा धनराशि निर्माण संस्था/विभाग को तब ही अवमुक्त की जायेगी, जब इस बात की लिखित रूप में पुष्टि हो जायें।



7. वास्तविक क्षति के कार्यों पर ही धनराशि स्वीकृत की जायेगी। सामान्य मरम्मत के कार्य प्राकृतिक आपदा की परिधि में नहीं आते हैं। अतः सामान्य मरम्मत के कार्यों, नव निर्माण तथा विकास कार्यों में धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

8. प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यों के मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय, कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, अनिश्चितता, गुणवत्ता तथा विभागीय मानकों की अवहेलना आदि के संबंध में जांच कर धनराशि के दुरुपयोग व अनियमित उपयोग की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध प्रथम दण्ड के रूप में वसूली, द्वितीय दण्ड के रूप में वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा तृतीय दण्ड के रूप में एफ.आई.आर. (F.I.R.) की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

9. प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यों के संबंध में उप जिलाधिकारी द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि के व्यय हेतु निर्धारित नवीन मद एवं मानकों से आच्छादित होने एवं निर्धारित समयावधि के अन्दर क्षति होने की पुष्टि तथा प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण कर सुस्पष्ट संस्तुति के बाद ही कार्य योजना सक्षम स्तर से स्वीकृत की जायेगी।

10. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबंधित जिलाधिकारी/निर्माण एजेन्सी/संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

11. कार्य स्वीकृत लागत में पूर्ण कर लिये जायेंगे। कार्य कराते समय वित्तीय नियमों एवं टेण्डर आदि तथा कार्यदायी संस्था के साक्ष्य किये गये एमओयू (M.O.U.) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य सम्पन्न होने के पूर्व क्षतिग्रस्त कार्ययोजनाओं की फोटो ली जायेगी। कार्य की सत्यता एवं गुणवत्ता का प्रमाणीकरण जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। तदनुसार ही कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर राज्य आपदा मोचन निधि से निर्मित कार्ययोजना का नाम, दिनांक तथा मद का नाम सीमेन्ट कोंक्रीट पर अंकित कर दिया जाय।

13. भारत सरकार द्वारा नामित एक स्वतंत्र एजेन्सी से भी जनपदों के कार्यों का निरीक्षण व मूल्यांकन किया जायेगा। अतः जनपद स्तर पर कार्यों में निरीक्षण हेतु जिलाधिकारी द्वारा टीम गठित की जायेगी, जिसके द्वारा कार्य की क्षति, धनराशि के सही उपयोग गुणवत्ता आदि की समीक्षा की जायेगी।

14. जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के साथ प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित किया जायेगा।

15. वित्तीय वर्ष 2012-13 तक राज्य आपदा मोचन निधि से जारी समस्त स्वीकृतियों तथा इसके सापेक्ष व्यय/समर्पित धनराशि का लेखा मिलान संबंधित जिलाधिकारी द्वारा महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में निश्चित रूप से प्रत्येक तीन माह में सुनिश्चित कराया जायेगा।

16. उपरोक्त निर्देशानुसार धनराशि स्वीकृत की जायेगी। राज्य आपदा मोचन निधि के व्यय हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों, समय-समय पर निर्मित शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों/प्रक्रिया का अनुपालन व होने पर संबंधित जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी एवं कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

17. स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2013 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। स्वीकृत की जा रही



धनराशि का कोषागार से आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जाये और यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वह उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

18. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्यय अनुदान संख्या-6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-05 राज्य आपदा मोचन निधि (90% केन्द्र पोषित)-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-00-13- आपदा राहत निधि से व्यय-42-अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

19. यह आदेश वित्त विभाग के अ. शा. संख्या-170 NP/XXVII-5/2013, दिनांक 19 फरवरी, 2013 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

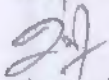
(भास्करानन्द)  
सचिव

संख्या-70(1)/XVIII-(2)/F/13-18(01)/2012 एवं तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 4- अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग।
- 5- कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
- 6- निजी सचिव, मा. मंत्री, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- राज्य सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9- प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10- बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड।
- 11- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 12- जनरल मैनेजर, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लि0, एन.बी.सी.सी. भवन लोदी रोड, नई दिल्ली-110003।
- 13- धन आवंटन संबंधी पत्रावली।
- 14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(संतोष बड़ोनी)  
अनु सचिव